

ग्रसाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उपलण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (H)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

संं० 268]

मई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1972/ज्येष्ठ 8, 1894

No. 2681

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1972/JYAISTHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

#### ORDERS

New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 381(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. S.O. 1027, dated the 6th March, 1971, the Management of the industrial undertaking known as Messers Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 6th day of March, 1971;

And whereas the Government of India is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry, namely, Railway Rolling Stock;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (l) of section 18-FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 6th day of March, 1971 shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 1/53/71-P.S.Cell/HM(I).]

## द्यौद्र∤गिक विकास मंत्रालय

### मावेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का० आ० 381 (आ).—यतः भारत सरकार के श्रीद्योगिक विकास श्रीर श्रान्तरिक व्यापार मंत्रालय (श्रीद्योगिक विकास विभाग) के श्रादेश सं० का० श्रा० 1027 तारीख 6 सार्च 1971 द्वारा नैसर्स श्रीयबट एण्ड कस्पनी (इणिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस श्रादेश में श्रागे श्रीद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तामक श्रीद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास श्रीर विनिमन) श्रिधनवम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के श्रिधीन 6 मार्च, 1971 से श्रारम्भ होने वाली श्रीवाच वर्ष की श्रवध के लिए ग्रहण कर लिया गया है;

श्रीर यतः भारत सरकार का समाधान हो गया है कि श्रनुसूचित उद्योग ग्रर्थात् रेल के भाल-डिज्बों के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से लोक हित में ऐसा करना श्रावश्यक है;

श्रतः, श्रवं, उक्त श्रधिनियमं की धारा 18 च ख की उनधारा (i) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वेदीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि ऐसी सभी संबिद्याएं, मम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंचाट. स्थायी श्रादेशया श्रन्य प्रवृत्त लिखतें, जिसका वह श्रीद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार था या तो 6 माच, 1971 से तुरन्त पूर्व उसे लागू रहे हों. निलम्बित रहेगे।

 वह श्रादेश राजपल में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अविधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा।

[सं० फा० 1/53/71अपी० एस० सेल/एच एम(1)]

S.O. 382(E)/IDRA/19/72/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 174(E)/IDRA/19/72/2, dated the 2nd March, 1972, namely:—

In the sald Order for item 3 relating to Shri S. Subha Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi the following item shall be substituted, namely:—

"3. Shri S. R. Mallya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Cost Accounts Branch, New Delhi."

[No. F.13(33)/Lic.Pol./70.]
S. M. GHOSH, Jt. Secy.

का० ग्रा० 382 (ग्र)/ग्राई जी ग्रार ए/19/72/4.— उद्योग (विकास तथा विनियमन) श्रिष्ठिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 19की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रकोग करते, हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के श्रीद्योगिक विकास मंत्रालय के श्रिध्सुचित श्रादेश सं० का० श्रा० 174 (ग्र)/श्राई डी श्रार ए/19/72/2, दिनांक 2 मार्च, 1972 में निम्न- लिखित संशोधन करती हैं, ग्रथांत :—

उक्त ग्रादेश में श्रो एस० सुभाराव, वरिष्ठ लागत लेखा ग्रधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्बन्धित मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात :──

> "श्री एस० म्रार० माल्या, वरिष्ठ लागत लेखा स्रधिकारी, वित मंत्रालय, लागत लेखा शाखा, नई दिल्ली ।"

> > [सं० फा० 13(33)/एल पी/79] एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

#### ORDERS

## New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 383(E)/IDRA/19/72/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 173(E)/IDRA/19/72/1, dated the 2nd March, 1972, namely:—

In the said Order for item 3 relating to Shri S. Subha Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi the following item shall be substituted. namely:—

"3. Shri S. R. Mallya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance. Cost Accounts Branch, New Delhi."

[No. F.13(33)/Lic.Pol./70.]

### श्रावेज

# नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का० ग्रा० 383(ग)/ग्राई की ग्रार ए/19/72/3.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) ग्रिक्षितियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के ग्रीचार्गिक विकास मंत्रालय, के भ्रिध्स्चित ग्रादेश सं० का० भ्रा० 173 (श्र)/भ्राई जी ग्रार ए/19/72/1, दिनांक 2 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं भ्रथात :—

उक्त श्रादेश में श्री एम०, सुभाराव, वरिष्ठ लागत लेखा श्रश्वकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से संबंधित मद 3 के स्थान पर निम्नलिखिन मद रखा जाएगा श्रशीत :---

> "श्री एस० म्रार० माल्या, वरिष्ठ लागत लेखा ग्राधिकारी, वित्त मंत्रालय, लागत लेखा शाखा, नई दिल्ली।"

> > [सं॰ एफ॰ 13(33)/एल॰ पी॰/70]

#### (Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 384(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O 143, dated the 9th January, 1967, read with the order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No S.O. 3251, dated the 30th August. 1971, the management of the industrial undertaking known as the Mahalakshmi Mills Company Limited, Bearwar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of seven years up to and inclusive of the 8th January, 1974.

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain scuspended for the said period.

[No. F.3/9/72-C.U.C.]

# (श्रीयोगिक विकास विमाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का॰ बा॰ 384(म्र).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार महालय के आदेश सं० का॰ ग्रा॰ 3251, तारीख 30 ग्रागस्त, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के भ्रादेश लंख्या का॰ ग्रा॰ 143 तारीख 9 जनवरी, 1967 द्वारा महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमि ड, बीवार, (जिसमें इसमें इसके पश्चात उक्त ग्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया हैं) के नाम से जात ग्रोद्योगिक उपक्रम का प्रबध, उद्योग (विकास भ्रोर विनियमन) ग्रिष्टिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18क के ग्रबीन मातवर्ष की श्रवधि तक ग्रोर जिसमें 8 जनवरी, 1974 भी सम्मिलत हैं ग्रहण कर लिया गया हैं:

श्रार यतः कंद्राय सरकार का समाधान हो गया हैं कि उक्त श्रोद्योगिक उपक्रम के बारे में जन-साधारण के हित में श्रनसूचित उद्योग, श्रयति सूतीवस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिमाण में कभी को रोकते की दृष्टि से ऐसा करना श्रावश्यक हैं;

श्रतः श्रव उन्त श्राधिनियम की धारा 18 च, ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एनदद्वारा घोषणा करती हैं कि इस ग्रादेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त बैंकों श्रोर वितीय सं थाग्रों के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित से भिन्न) सभी संधिदाश्रों, संपत्ति के हम्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यत्थापनों, श्रिधिनिर्णयों, स्थायी श्रादेशों या ग्रन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका उन्त श्रोद्योगिक उपक्रम या ऐसे श्रोद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वालो कोई कंपनो पक्षकार है या जो ऐसे श्रोद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हैं, एक वर्ष की श्रविष के लिए निर्लबित रहेगा श्रोर उन्त नारीख के पूर्व तद्यीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यताएं श्रोर दायित्व उन्त श्रविष के लिए निर्लबित रहेगें।

[नं० फा० 3/9/72-सी यु० सी०]

S.O. 385(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 4028/IDRA/18A/71 dated the 19th October, 1971, the management of the industrial undertaking known as the Mysore Spinning and Manufacturing Company Limited, Bangalore (hereinafter referred to as the said industrial undertaking has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 18th October, 1976:

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or others instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.3/8/72-C.U.C.]

का० आ० 385 (म).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व श्रौद्योगिक विकास श्रीर श्रान्तिरिक व्यापार मंत्रालय (श्रौद्योगिक विकास विभाग) के श्रादेश का ० श्रा० संख्या 4028/श्राई० डी०थार०ए०/18/71 तारीख 19 श्रक्तूबर, 1971 के द्वारा, मैसूर स्पीतिंग एण्ड मैन्युफैस्वरिंग कम्पनो लिमिटेड, बंगलौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम मे ज्ञात श्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास श्रौर विनियमन) श्रिक्षित्यम, 1951 (1951 का 65)की धारा 188

के अधीन पांच वर्ष की श्रवधि तक श्रौर जिसमें 18 श्रक्तूबर 1976 भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है:

श्रौर यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्रोद्योगिक उपक्रम के बारे में, जनसाधारण के हित में, श्रनुसूचित उद्योग श्रर्थात् सूती वस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना श्रावस्यक है;

अतः श्रव उक्त श्रिधिनियम की धारा 18 जख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक, पूर्व प्रवृत (बैकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्यों से संबंधित से भिक्ष) सभी संविदाओं संपत्ति के हस्तातरण,पत्नों, करारों, व्यवस्थापनों, श्रिधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या श्रन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्य करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की भ्रवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तरीख के पूर्व तदधीन उत्पन्न या उद्मूत होने वाली सभी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त श्रवधि के लिए निलंबित रहेंगे।

[नं॰ फा॰ 3/8/72-सी॰ यू॰ सी॰]

S.O. 386(E). Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 4030/18A/IDRA/71, dated the 19th October, 1971, the management of the industrial undertaking known as the M/s. Minerava Mills Limited, Bangalore (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 18th October, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing of arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.3/8/72-C.U.C.], S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 386(म) — यतः भारत सरकार के भूतपूर्व ग्रौद्योगिक विकास भीर ग्रान्तरिक व्यापार मंत्रालय (ग्रौद्योगिक विकास विभाग) के ग्रादेश का० ग्रा० संख्या 4030/18 क/ग्राई डी ग्रार ए/71 सारीख 19 ग्रक्तूबर, 1971 द्वारा, मैंसर्स भिर्वा मिल्स लिमिटेड, बंगलौर (जिसे इसमें इसके परवात उक्त श्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम ज्ञात श्रौद्योगिक उपक्रम का प्रवन्ध, उद्योग (विकास भौर विनियमन) ग्रिधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के के श्रधीन पांच वर्ष की श्रविध तक श्रौर जिसमें 18 श्रक्तूबर, 1976 भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है:

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्रीद्योगिक उपक्रम के बारे में जनसाधारण के हित में, श्रनुसूचित उद्योग, श्रर्थात्, सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन के परिणाम कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना श्रावश्यक है;

श्रतः अब उक्त श्रिष्ठित्यम की धारा 18वख की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इस ग्रादेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत (बैंकों ग्रौर वित्तीय संस्थाग्रों के प्रतिभूत दायित्यों से संबंधित से भिन्न) मभी संविदाश्रों, संपत्ति के हस्तातरण-पत्नों, करारों, व्यवस्थापनों, श्रिष्ठितिणेयों, स्थायी श्रादेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन जिनका उक्त श्रौद्योगिक उपक्रम या ऐसे श्रौद्योगिक उपक्रम का स्वामित्य करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है या जो ऐसे श्रौद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की ग्रविध के लिए निलंबित रहेगा श्रीर उक्त तारीख के पूर्व तद्यीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी ग्रिष्ठकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं श्रौर दायित्व उक्त श्रविध के लिए निलंबित रहेंगे।

[सं० फा० 3/8/72—सी० यू० सी•] एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।